

अरपं भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

मंगलवार 12 जून 2024

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेट

मनोज जरांगे का
अनशन जारी

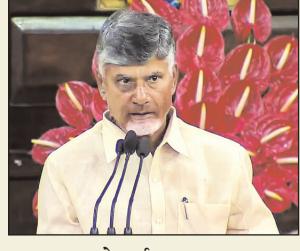
मुंबई आरक्षण से संबंधित मांगों को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे शनिवार से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। अनशन के चार दिन बाद, मंगलवार को डॉक्टरों की सलाह के बावजूद उन्होंने नसों के माध्यम से तरल पदार्थ (आई प्ल्यूड) लेने से इनकार कर दिया। जरांगे ने शनिवार को महाराष्ट्र के जालना जिले में अंतर्राजी स्तरीय गांव से नए सिरे से भूख हड्डियां शुरू की हैं। बता दें कि वह मराठा सम्पदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओवीसी) के तहत आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। जरांगे ने तरल पदार्थ लेने से किया इनकार: सरकारी ग्रामीण अस्पताल के एक दल ने आज सुबह उनकी जांच की। इस दौरान उनकी ब्लड प्रेशर और शुगर स्तर कम था। डॉक्टरों ने उन्हें नसों के माध्यम से शरीर में तरल पदार्थ लेने की सलाह दी। मीडिया से बात करते हुए एक डॉक्टर ने इसकी जानकारी दी। हालांकि, जरांगे ने इस तरह से आहार लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने विद्या से कहा, "ऐसा लाला है कि सरकार को हमारी दुर्दशा की बिलकुल चिंता नहीं है। मराठा समुदाय उन्हें सबक सिखाएगा।" मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे से जब महाराष्ट्र के मंत्री और ओवीसी नेता छान भुजबल के इस बयान के बरे में पूछे जाएंगे पर कि सरकार द्वारा मराठाओं को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण न्यायिक जांच में खरा उतराया, इस पर उन्होंने कहा कि भुजबल को इस मुंबई पर उत्तरक्षण नहीं है। बता दें कि जरांगे मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाणपत्र देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल, महाराष्ट्र में कुंभी समुदाय को ओवीसी श्रेणी में रखा गया है ऐसे में मराठा आरक्षण के लोगों को कुंभी जाति प्रमाणपत्र देने से उन्हें (मराठा आरक्षण के लोगों को) आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

वित्त विभाग महीनों से बेरोजगारी भर्ते के बिलों को रोककर बैठा:

गहोलत

जयपुर: सरकार में लंबित विलों के भुगतान को लेकर लागतान नए-एनए मालों समें आ रहे हैं। पूर्ण सौंपें अंशोक गहलोत ने प्रदेश की भजलाल सरकार पर बेरोजगारी भता रोकने का बड़ा आपेक्षा लाता हुए कहा है कि वित्त विभाग महीनों से बेरोजगारी भर्ते के बिलों को रोककर बैठा है।

चंद्रबाबू नायडू चुने गए एनडीए विधायक दल के नेता



जांबंदर नें जनसेना पार्टी के विधायकों ने अपना नेता चुना। तेदेपा को मिला जबरदस्त समर्थन आंद्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 सीटों में से 135 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यहां कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती हैं और भाजपा को भी आठ सीटें पर जीत हासिल हुई है। वहाँ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वार्षिसस्आरसीपी महज 11 सीटें पर सिंहट गयी हैं। आंद्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेदेपा, जनसेना और भाजपा गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी।

जांबंदर नें जनसेना पार्टी के विधायकों ने अपना नेता चुना। तेदेपा को मिला जबरदस्त समर्थन आंद्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की 175 सीटों में से 135 सीटें जीतकर चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। यहां कल्याण की जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती हैं और भाजपा को भी आठ सीटें पर जीत हासिल हुई है। वहाँ जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वार्षिसस्आरसीपी महज 11 सीटें पर सिंहट गयी हैं। आंद्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेदेपा, जनसेना और भाजपा गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतरी थी।

इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है।

प्रशांत किशोर ने यह बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। वहाँ, एनडीए के घटक दलों के साथ आंकड़ा 292 पर पहुंचा। बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोग टीडीपी और जदयू ने किया। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं। वहाँ, नीतीश की जदयू ने 12 सीटों पर परचम लहराया। दोनों दलों का साथ एनडीए 3.0 के लिए बहुत जरूरी है।

कहा कि उनकी सबसे बड़ी नीति को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। सूत्रों की माने तो वह नीति मोदी 3.0 सरकार के 100 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री अंजुन राम मेघवाल ने

माले जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि दस्तावेज में लंबित पड़े मालों के त्वरित समाधान का जिक्र किया गया है। बताया कि वह पहला काम था, जिसे केंद्रीय मंत्री सबसे पहले निपटाना चाहते थे। बता दें कि राष्ट्रीय मुकदमा नीति का मार्फत पहले निपटाना चाहता है। केंद्रीय मंत्री सबकारों में कई बातें तेवर बिया गया। कई वर्षों से सरकारों द्वारा इसकी रूपरेखा पर विचार-विमर्श किया गया। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि नई नीति के पास होने से लंबित पड़े मालों पर तुरंत बदलाव नहीं होगा और आप जनता को आसानी होगी।

कहा कि उनकी सबसे बड़ी नीति को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि नई नीति के पास होने से लंबित पड़े मालों पर तुरंत बदलाव नहीं होगा और उपभोक्ता अदालतों में लंबित पड़े मालों की न्याय प्रक्रिया में तेजी लाना है। इसकी आसानी होगी।

शाह ने फिर संभाला गृह मंत्रालय का प्रभार



नई दिल्ली

राज्य मंत्री और एल. मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं, केंद्रीय मंत्री सुशेष गोपी ने पर्यावरण मंत्रालय के राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। साथ ही डॉ. जिंटेंड्र सिंह को कार्यकारी और पैसेंजर मंत्रालय में राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री हरीष्वर पर्यावरण पर्यावरण एवं विकास को लेकर राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। राजीव रंजन(ललन) सिंह ने पंचायती राज मंत्री और भरतीय राजनीतिक विकास को लेकर राज मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर पैसेंजर मंत्री ने एक बार फिर भरतीय राजनीतिक विकास को लेकर राज मंत्री का कार्यभार संभाला। वहीं, सहकारिता मंत्री का कार्यभार संभाला। किरन रिजु, ने संसदीय संसद चलाने में सबसे बोगदान चाहिए।

देश के जने-माने राजनीतिक विकास को लेकर चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। वहाँ, एनडीए के घटक दलों के साथ आंकड़ा 292 पर पहुंचा। बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोग टीडीपी और जदयू ने किया। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं। वहाँ, नीतीश की जदयू ने 12 सीटों पर परचम लहराया। दोनों दलों का साथ एनडीए 3.0 के लिए बहुत जरूरी है।

इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की। वहाँ, एनडीए के घटक दलों के साथ आंकड़ा 292 पर पहुंचा। बीजेपी का सबसे बड़ा सहयोग टीडीपी और जदयू ने किया। टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं। वहाँ, नीतीश की जदयू ने 12 सीटों पर परचम लहराया। दोनों दलों का साथ एनडीए 3.0 के लिए बहुत जरूरी है।

इंटरव्यू में कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरा देता है तो केंद्र में मंत्री की सरकार को दिक्षित आ

सकती है। बता दें कि अगर विपक्षी गठबंधन यारी आईएनडीआईए आंद्रोलोगो विधानसभा चुनाव

संपादक की कलम से

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहेगा बेरोजगारी संकट

प्रधानी आर्थिक विकास के बाबजूद, देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी का संकट भयावह बना हुआ है, जो मोदी सरकार द्वारा 2014 से अपनाये जा रहे रोजगार रहित विकास मॉडल का प्रमाण है। लोकसभा के नतीजों ने पीएम मोदी को लोकसभा में बहुमत से चुनित किया, जो उनके लिए और सरकार में एनडीए सहयोगियों के लिए भी एक सबक है। 2014 के बाद से जारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले दो कार्यकालों में अभूतपूर्व बेरोजगारी सकट उनके तीसरे कार्यकाल में भी जारी रहने की संभावना है, जब तक कि वर्तमान रोजगारहीन विकास मॉडल में बदलाव नहीं किया जाता। लगभग एक अरब कामकाजी आयुर्वर्ग की आबादी में से, पिछले कुछ वर्षों से रोजगार में लगे लोगों की संख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास रही है, जो चिंता का विषय है। इस भवावह जमीनी हकीकत के बाबजूद, प्रधानमंत्री मोदी और उनका सरकार के अधिकारी दावा करते रहे कि बेरोजगारी दर में गिरावट अपर्ही है। यहां तक कि सरकार के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से पता चला है कि 2022-23 के दौरान बेरोजगारी दर गिरकर 3.1 प्रतिशत हो गयी है। हालांकि, गैर-सरकारी सीएमआई के ताजा रियल टाइम आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी 7-8 प्रतिशत के आसपास मंडराती रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान, जब बेरोजगारी मतदाताओं के बीच एक प्रमुख मुद्दा बन गयी, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने एक बयान दिया कि 2022-2023 में 30 मिलियन नौकरियां पैदा करके गयीं और पिछले पांच वर्षों में 110 मिलियन से अधिक नौकरियां जोड़ी गयीं। इसका मतलब यह था कि मोदी सरकार ने देश के बेरोजगारी संकट को पहले ही हल कर दिया था, क्योंकि हर साल लगभग 20 मिलियन लोग ही भारतीय श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इसका यह भी मतलब था कि मोदी सरकार ने एक साल में 30 मिलियन नौकरियां पैदा करके जरूरत से ज्यादा काम किया। डावरा ने यह बयान भारतीय रिजर्व बैंक के केएलईएमएस डेटाबेस के 2022-23 के अंतिम आंकड़ों का हवाला देते हुए दिया था, जो पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवा क्षेत्रों में रोजगार सृजन और उत्पादकता के स्तर को ट्रैक करता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डावरा के दावे का समर्थन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के वार्षिक पीएलएफएस डेटा से भी नहीं होता है। यहां यह याद रखना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान साल 20 मिलियन नौकरियां देने का वायदा किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ, यहां तक कि हर साल जारी होने वाले सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी नहीं। लेकिन अचानक मोदी सरकार के श्रम सचिव ने पिछले महीने मई में कहा कि पिछले साल 30 मिलियन नौकरियां पैदा हुईं। मार्च में हर्ष मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा था कि यह मान लेना गलत है कि सरकार बेरोजगारी जैसी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल कर सकती है। उन्होंने यह बयान नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और मानव विकास संस्थान (आईएचडी) के संयुक्त प्रकाशन 'भारत रोजगार रिपोर्ट 2024: युवरोजगार, शिक्षा और कौशल' के लॉन्च के दौरान दिया था। सीईएस संसांदीय दल की नेता चुने जाने के बाद उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे हार गए हैं। नेतृत्व करने का अधिकार खो चुके हैं। सोनिया को अब यह सब कहने और करने की जरूरत नहीं है। राहुल, प्रियंका और पार्टी नई ताकत के साथ सामने आए हैं। मोदी को साधारण बहुमत से भी पीछे रोक दिया गया है। मगर जैसा कि खुद सोनिया ने कहा और सही कहा कि वे स्वभाव से शेरनी हैं।

मैं शेरनी हूं!

- शकील अख्तर

आज ममता बनर्जी की बहुत बात की जा रही है। विपक्ष में सीटें जीतने के मामले में वह तीसरे नंबर पर रहीं। बंगाल में उन्होंने मोदी को रोक दिया। कांग्रेस सौ के बाद सपा 37 और ममता 29 पर रहीं। तो ममता का जिक्र हम इसलिए कर रहे थे कि उस समय 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो वे सोनिया से मिलकर उन्हें पूरी बात बता कर गई थीं कि कैसे नरसिंहा राव सीताराम के सरीब बंगाल के नेताओं से मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

सोनिया गांधी ने कहा मजाक में मगर यह सबसे सही है। मैं शेरनी हूं। वाकई एक शेरनी की तरह वह लगातार लड़ रही हैं। कांग्रेस संसांदीय दल की नेता चुने जाने के बाद उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे हार गए हैं। नेतृत्व करने का अधिकार खो चुके हैं। सोनिया को अब यह सब कहने और करने की जरूरत नहीं है। राहुल, प्रियंका और पार्टी नई ताकत के साथ सामने आए हैं। मोदी को साधारण बहुमत से भी पीछे रोक दिया गया है। मगर जैसा कि खुद सोनिया ने कहा और सही कहा कि वे स्वभाव से शेरनी हैं।

राहुल का सबसे बड़ा गुण उनकी निरुद्धता माना जाता है। पिछले दस साल में जब अच्छे-अच्छे डर गए। व्यक्ति क्या संवैधानिक संस्थाएं डर गईं तब भी राहुल डटे रहे। इसी पृष्ठभूमि में अमेठी से जीते किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने राहुल के लिए सोनिया गांधी को से कहा कि आपने शेर बच्चा पैदा किया है।

दरअसल किशोरी लाल शर्मा का परिवार पंजाबी में आम मुहावरा है- शेर पुत्र! वही उन्होंने हन्दी में कहा। और सोनिया ने हंस कर जवाब दिया कि मैं भी तो शेरनी हूं।

इस दिलचस्प वाकये के एकाध दिन पहले ही हमने ट्रीटीट किया था कि संजय गांधी के लाइके को डरते हुए देखना बहुत दुखद है। हमने उसमें कहा था कि सिर्फ डीएनए ही कुछ नहीं होता है वह परवरिश, माहौल भी बड़ी चीज होती है। जिसने संजय गांधी को देखा है वह जानता है कि डर और दबना क्या होता है वह संजय जानते ही नहीं थे। उन्हीं के बेटे वरुण को जब भाजपा ने टिकटट नहीं दिया तो वे चुप रहे। सब सोचते थे कि वे निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जर्बार्दस्त सफलता मिली है उस माहौल में वरुण का जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ठीक है वह नहीं लड़े लेकिन फिर उन्होंने भाजपा का भी प्रचार किया। मेनका गांधी भी हारीं। और उनकी राजनीति खत्म हो गई। मगर इसके साथ मेनका ने बेटे का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा दिया। वरुण की पहचान गांधी होने के कारण ही थी। और केवल नाम से टाइटल से कुछ नहीं होता है। वह गुण परिवार का आना चाहिए।

मैं शेरनी हूं!

- शकील अख्तर

आज ममता बनजा को बहुत बात को जा रही है। विपक्ष में सटीकीतने के मामले में वह तीसरे नंबर पर रहीं। बंगाल में उन्होंने मोदी को रोक दिया। कांग्रेस सौ के बाद सप्ता 37 और ममता 29 पर रहीं। तो ममता का जिक्र हम इसलिए कर रहे थे कि उस समय 1997 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो वे सेनिया से मिलकर उन्हें पूरी बात बता कर गई थीं कि कैसे नरसिंहा राव सीताराम के सरीब बंगाल के नेताओं से मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हैं।

सोनिया गांधी ने कहा मजाक में मगर यह सबसे सही है। मैं शरनी हूँ। वाकई एक शेरनी की तरह वह लगातार लड़ रही है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने के बाद उन्होंने मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे हार गए हैं। नेतृत्व करने का अधिकार खो चुके हैं। सोनिया को अब यह सब कहने और करने की जरूरत नहीं है। राहुल, प्रियंका और पार्टी नई ताकत के साथ सामने आए हैं। मोदी को साधारण बहुमत से भी पांछे रोक दिया मगर जैसा कि खुद सोनिया ने कहा और सही कहा कि वे स्वभाव से शेरनी हैं।

राहुल का सबसे बड़ा गुण उनकी निडरता माना जाता है। पिछले दस साल में जब अच्छे-अच्छे डर गए। व्यक्ति क्या संवैधानिक संस्थाएं डर गईं तब भी राहुल डटे रहे। इसी पृष्ठभूमि में अमेठी से जीते किशोरी लाल शर्मा की पत्नी ने राहुल के लिए सोनिया गांधी से कहा कि आपने शेर बच्चा पैदा किया है।

दरअसल किशोरी लाल शर्मा का परिवार पंजाबी हैं। और पंजाबी में आम मुहावरा है- शेर पुत्तर! वही उन्होंने हिन्दी में कहा। और सोनिया ने हंस कर जवाब दिया कि मैं भी तो शेरनी हूं। इस दिलचस्प वाकये के एकाध दिन पहले ही हमने ट्रैवट किया था कि संजय गांधी के लड़के को डरते हुए देखना बहुत दुखद है हमने उसमें कहा था कि सिर्फ डीएनए ही कुछ नहीं होता है परवरिश, माहौल भी बड़ी चीज होती है। जिसने संजय गांधी को देखा है वह जानता है कि डर और दबना क्या होता है वह संजय जानते ही नहीं थे। उन्हीं के बेटे वरुण को जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वे चुप रहे। सब सोचते थे कि वे निर्दलीय या किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जबर्दस्त सफलता मिली है उस माहौल में वरुण का जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। मगर ठीक है वह नहीं लड़े लेकिन फिर उन्होंने भाजपा का भी प्रचार किया। मेनका गांधी फिर भी हारीं। और उनकी राजनीति खतम हो गई। मगर इसके साथ मेनका ने बेटे का राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लगा दिया। वरुण की पहचान गांधी होने के कारण ही थी। और केवल नाम से टाइटल से कुछ नहीं होता है। वह गुण परिवार का आना चाहिए।

संसद में दार्ढी नेताओं की संख्या बढ़ना विज्ञाजनक



-ललित गर्ग-
देश में 18वीं लोकसभा चुनी जा चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और रिकॉर्ड संख्या में मतदाता होने के गर्व करने वाली स्थितियां हैं वहीं चिन्ताजनक, विचलित एवं पेशान करने वाली स्थितियां भी हैं। खबर आई है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंटप में पहुंचने वाले 543 सांसदों में 46 फीसदी आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं जो पिछली बार से तीन प्रतिशत अधिक है। भारतीय राजनीति में आपराधिक छवि वाले या किसी अपराध के आरोपी का सम्पन्ना कर रहे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाए जाने एवं उन्हें राष्ट्र-निर्माण की जिम्मेदारी दिया जाना-हर नागरिक के माथे पर चिंता की लकड़ी लाने वाली है। क्या इस स्थिति में देश की लोकतांत्रिक शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा हो पाएगी? क्या हम आदर्श एवं मूल्यपरक समाज बना पाएंगे? क्या ये दागदार नेता एवं जन-प्रतिनिधि कालांतर हमारी व्यवस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मसलों का विश्लेषण करने वाली सचेतक संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपोर्टर्स की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2019 में चुने गये सांसदों में जहां 233 यानी 43 फीसदी ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की थी, वहीं अठाहरवीं लोकसभा के लिये चुने गए 251 सांसदों ने आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। जो कुल संख्या का 46 फीसदी बैठती है।

आज भारत की आजादी के अमृतकाल का एक बड़ा प्रश्न है भारत की राजनीति को अपराध मुक्त बनाने का। यह बेवजह नहीं है कि देशभर में अपराधी तत्वों के राजनीति में बढ़ते दखल ने एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी है जिसका अपहरण के आरोपी अदालत में पेश होने की जगह मंत्री पद का शपथ लेने पहुंच जाते हैं। अरविन्द केजरीवाल जैसे नेता आम चुनावों में कहते हैं कि आप लोग बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के बोट दें ताकि मैं जेल जाने से बच सकूं। हम ऐसे चरित्रहीन एवं अपराधी तत्वों को जिम्मेदारी वे पद देकर कैसे सुशासन एवं ईमानदार व्यवस्था स्थापित करेंगे? कैसे आम जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे? कैसे संसद में दायित्व के पहुंचने के लिये द्वारा बंद होंगे दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की सज्जन पहल पर ही वर्ष 2020 से सभी राजनीतिक दल लोकसभा विधानसभा के उम्मीदवारों वे आपराधिक रिकॉर्ड को प्रकाशित करने लगे हैं। निश्चित ही इस आदेश का मकसद देश के राजनीति को आपराधिक छवि वाले नेताओं से मुक्त करना है था। लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों की प्राथमिकता जीतने वाले उम्मीदवार थे, अब चाहे उनका आपराधिक रिकॉर्ड ही क्यों न हो वह बड़ा प्रश्न है कि अखिर राजनीति में तब कौन आदर्श उपस्थिति करेगा? क्या हो गया उन लोगों का जिन्होंने सदैव ही हर कुबानी करके आदर्श उपस्थिति किया। लाखों लोगों के लिए अनुकरणीय बने, आदर्श बने। चाहे आजादी की लड़ाई हो विजयी हो देश की सुरक्षा हो, धर्म की सुरक्षा हो, अपने वचन की रक्षा हो, अथवा अपनी संस्कृति और अस्मिता की सुरक्षा का प्रश्न हो वह उन्होंने फर्जी और वचन निभाने वे लिए अपना सब कुछ होम दिया था। महाराणा प्रताप, भगत सिंह, दुगार्दास, छत्रसाल, शिवाजी जैसे वरोंने अपनी तथा अपने परिवारों की सुख-सुविधा को गौण कर बड़ी कुबानी दी थी। गुरु गोविन्दसिंह ने अपने दोनों पुत्रों का

दावाव में चिनवा दिया और पन्नाधाय ने अपनी स्वामी भक्ति के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। ऐसे लोगों का तो मन्दिर बनना चाहिए। इनके मन्दिर नहीं बने, पर लोगों के सिर श्रद्धा से झुकते हैं, इनका नाम आते ही। लेकिन आज जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय जीवन और सोच विकृत हुए हैं, हमारी राजनीति स्वार्थी एवं सकीर्ण बनी है, हमारा व्यवहार झूठा हुआ है, चेहरों से ज्यादा नकाबें ओढ़ रखी हैं, उसने हमारे सभी मूल्यों को धराशायी कर दिया। राष्ट्र के करोड़ों निवासी देश के भविष्य को लेकर चिन्ता और ऊहापोहे में हैं। वक्त आ गया है जब देश की संस्कृति, गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने के लिए कुछ शिखर के व्यक्तियों को भागीरथी प्रयास करना होगा। दिशाशून्य हुए नेतृत्व वर्ग के सामने नया मापदण्ड रखना होगा। अगर किसी हत्या, अपहरण या अन्य संगीन अपराधों में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसे राजनीतिक बता कर संरक्षण देने की कोशिश या राजनीतिक लाभ उठाने का कुछांश पर लगाना ही होगा। प्रधानमंत्री ने मोदी ने भ्रष्टाचार एवं अपराध राजनीति को सदैव प्राथमिकता लेकिन चुनाव जीतने के रण भी अपराधी राजनेताओं को प्रदेते हुए दिखे हैं। सभी राजनीति दलों ने ही दामी उम्मीदवारों द्विकट दिए हैं। जो राजनीति दलों की कथनी और करनेवाली भारी अंतर को ही उजागर करती है कि देश के नीति निर्धारण करने वाले दामी लोग हमारे भाग्यविधाता रहेंगे तो हमारा भविष्य नहीं होगा? क्या आपराधिक पृष्ठ वाले लोग जनप्रतिनिधि चुने के बाद हमारी कानून-व्यवस्था प्रभावित नहीं करेंगे? क्या हमारे समाज व व्यवस्था भविष्य? क्यों तमाम आदर्शों बात करने वाले और दूसरे के नेताओं की कारगुजारी ये सवाल उठाने वाले नेता राजनीति को अपराधियों के वर्चस्व से कराने की ईमानदार पहल करते? क्यों सभी राजनीतिक भारतीय लोकतंत्र में शुचिता

पवित्रता के लिये सहमति नहीं बनाते ? निश्चित रूप से यदि समय रहते इस दिशा में कोई गंभीर पहल नहीं होती तो आने वाले वर्षों में दागियों का यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जाएगा । इसके साथ ही बड़ा संकट यह भी है कि देश के निचले सदन में येन-केन-प्रकारेण करोड़पति बने नेताओं का वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा है । इस बार संसद में चुनकर आए सासदों में 504 करोड़पति हैं । ऐसे में क्या उम्मीद की जाए कि अपनी मेहनत की कमाई से जीवनयापन करने वाला आम आदमी कभी सांसद बनने की बात सोच सकता है ? दागी एवं अपराधी राजनेता लोकतंत्र की एक बड़ी विडम्बना एवं विसंगति बनते जा रहे हैं । बात लोकसभा की ही नहीं है, विभिन्न राज्यों की सरकारों में भी कैसा विरोधाभास एवं विसंगति है कि एक अपराध छवि वाला नेता कानून मंत्री बन जाता है, एक अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है । ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय के साथ होता है । यह कैसी विवशता है राजनीतिक दलों की ? अक्सर राजनीति को अपराध मुक्त करने के दावे की हकीकत तब सामने आ जाती है जब किसी राज्य या केंद्र में गठबंधन सरकार के गठन का मौका आता है । यह खुशी की बात है कि केन्द्र में बनी गठबंधन सरकार के मंत्रिमण्डल में ऐसी विवशता को काफी सीमा तक नियंत्रित किया गया है । सीमाओं पर राष्ट्र की सुरक्षा करने वालों की केवल एक ही मांग सुनने में आती है कि मरने के बाद हमारी लाश हमारे घर पहुंचा दी जाए । ऐसा जब पढ़ते तो हमारा मस्तक उन जवानों को सलाम करता है, लगता है कि देश भक्ति और कुबानीं का मादा अभी तक मरा नहीं है । लेकिन राजनीति में ऐसा आदर्श कब उपस्थित होगा ।

राजनीति में चरित्र एवं नैतिकता के दीये की रोशनी मन्द पड़ गई है, तेल डालना होगा । दिल्ली सरकार में मंत्रियों के घरों पर सीबीआई के छापे और जेल की सलाखें हो या बिहार मंत्री परिषद के गठन में अपराधी तत्वों की ताजपोशी-ये गंभीर मसले हैं, जिन पर राजनीति में गहन बहस हो, राजनीति के शुद्धिकरण का सार्थक प्रयास हो, यह नया भारत -सशक्त भारत की प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए ।

सभी अपनी-अपनी पहचान एवं स्वार्थपूर्ति के लिए दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं । कोई पैसे से, कोई अपनी सुदरता से, कोई विद्वान् से, कोई व्यवहार से अपनी स्वतंत्र पहचान के लिए प्रयास करते हैं । राजनीति की दशा इससे भी बदतर है कि यहां जनता के दिलों पर राज करने के लिये नेता अपराध, भ्रष्टाचार एवं चरित्रहीनता का सहारा लेते हैं । जातिवाद, प्रांतवाद, साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर जनता को तोड़ने की कोशिशें होती हैं । पर हम कितना भ्रम पालते हैं । पहचान चरित्र के बिना नहीं बनती । बाकी सब अस्थायी है । चरित्र एक साधना है, तपस्या है । जिस प्रकार अहं का पेट बड़ा होता है, उसे रोज कुछ न कुछ चाहिए । उसी प्रकार राजनीतिक चरित्र को रोज संरक्षण चाहिए और यह सब दृढ़ मनोबल, साफ छवि, ईमानदारी एवं अपराध-मुक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है । राजनीति में चरित्र-नैतिकता सम्पन्न नेता ही रेस्पेक्टेबल (सम्माननीय) हो और वही एक्सेप्टेबल (स्वीकार्य) हो ।

प्रेषक:
(ललित गर्ग)

ई-253, सरस्वती कुंज-अपार्टमेंट
25 आई॰ पी॰ एक्सेंटेशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोन: 22727486,

प्रधकः
(ललित गर्ग)
ई-253, सरस्वती कुंज
अपार्टमेंट
25 आई० पी० एक्सटेंशन,
पटपड़गंज, दिल्ली-92
फोनः 22727486,

ਮਜਬूਰਾ ਫਾ ਨਾਮ ਏਨਡਾਈ

राजस्त्र रा।

का चुनाव था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बराबरी के मुकाबले की यह न्यूनतम से न्यूनतम शर्त भी पूरी नहीं हो रही थी कि चुनाव आयोग, जिस पर खतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व था, कम से कम निष्पक्ष दिखाई देने की कोशिश करेगा। बेशक, 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन के कोटाईर्याड में पूरे बहतर सदस्यों के जंबो मर्मिंडल के शृणु ग्रहण के साथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरी पारी

नानमंडल के राष्ट्रपत्रियों के तीसरी पारी का नेतृत्व पाला सरकार का रास्ता पारा शुरू हो गयी है। लेकिन, यह तीसरी पारी कितनी असामान्य होने जा रही है, इसका अंदाजा एक इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में कौन जीता है और कौन हारा है, इसके विवाद पर सरकार के शपथग्रहण के बावजूद, संतोषजनक तरीके से विराम नहीं लग पाया है। इसमें शक नहीं कि 4 जून को देर शाम 18वीं लोकसभा के चुनाव की मतगणना लगभग पूरी होने तक, जब इंडिया गढ़वंधन की गिनती 240 पर रुक गयी और दूसरी ओर भाजपा और उसके 2024 के चुनाव के सहयोगियों की गिनती बहुमत के 272 के आंकड़े को पार कर 290 पर पहुंच गयी, तभी इतना तो सभी यथार्थवादी प्रेक्षकों के सामने साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ जरूर लेंगे। यह इसके बावजूद था कि कुल मिलाकर इस चुनाव में जिस तरह का जनादेश आया है, उसे देखते हुए खुद संघ-भाजपा के समर्थकों के भी एक हिस्से को यह मानने में हिचक थी कि इस चुनाव का फैसला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जारी रहने के पक्ष में है। 2024 के चुनाव से निकली लोकसभा सदस्यों की गिनती बेशक, भाजपा और उसके सहयोगियों के मिलकर सरकार बनाने का रास्ता बनाती थी, लेकिन इस चुनाव का जनादेश कठु और ही कह रहा था।

यह किसी से छुपा हुआ नहीं था कि यह चुनाव, भारत का अब तक का सबसे नवबाबरी का चुनाव था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बराबरी के मुकाबले की यह न्यूनतम से न्यूनतम शर्त भी पूरी नहीं हो रही थी कि चुनाव आयोग, जिस पर खंतिर व निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व था, कम से कम निष्पक्ष दिखाई देने की कार्रिए करेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर सत्ताधारी पार्टी, चुनावी मुकाबले में विपक्ष को पंगु करने के लिए, शासन के सभी दमनकारी साधनों का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए, जिसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने से लेकर विपक्षी पार्टियों के खाते जाम करना तक शामिल था। निष्पक्षता की बजियां उड़ा रही थीं। तो दसरी ओर सत्ताधारी पार्टी को अपन

शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक, विपक्ष के खिलाफ सांसदों जा रहे थे। उनमें से कई अपने दृष्टिकोण के बावजूद और सांग्रहायिक प्रवारों को हथियार बनाने के जरिए, जनता के जानकारी पर आधारित चुनाव करने के अधिकार की जड़ें ही काटने की खुली छूट मिली हुई थी। इसके ऊपर से सत्ताधारी पार्टी को मुख्यमान के मीडियों को न सिर्फ पैसे तथा मीडिया धन्नासेठों के समर्थन के बल पर अपने लिए छेक लेने का बल्कि तह-तरह के सर्वक्षणों के जरिए उसे मारक हथियार बनाने का और कुल मिलाकर बेशुमार पैसा बहाने तथा विपक्ष के संसाधनों के सारे स्रोत सुखाने का भी, मौका मिला हुआ था। इसके बावजूद, इस चुनाव में जनता ने जो फैसला

सुनाया था, साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ था। बेशक, चार सौ पार के जो दाव सत्तापक्ष और उसके मीडिया में छाए प्रचारकों द्वारा विधिवत चुनाव प्रचार शुरू होने से महीनों पहले से शुरू कर, एकजंत पोलों तक के जरिए किए जा रहे थे, उन सबके समाने, सत्ताधारी भाजपा का 240 के आंकड़े पर और सहयोगियों को भी जोड़कर, 292 के आंकड़े पर अटक जाना भी, किसी हार से कम नहीं था। लेकिन, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इससे बड़ी बात यह थी कि जहाँ अकेले भाजपा के 370 पार और संगियों के साथ मिलकर चार सौ पार जाने का दम भरा जा रहा था, जब नतीजे आए भाजपा खुद 240 सीटों पर सिमट गयी और सहयोगियों के साथ मिलकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा पार कर पायी। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में भाजपा को जो 303 सीटें हासिल हुई थीं, उनमें पूरे 20 फीसद यानी 63 सीटों की कमी इस चुनाव में जनता ने कर दी और उसके गठजोड़ की सीटों में से भी करीब इतनी ही कमी। साफ है कि जनता ने पिछले चुनाव के मुकाबले, सत्ताधारी दल और उसके गठजोड़ को दुकराया ही है, उसे अपनी करनियों और अकरनियों के लिए राजनीतिक सजा ही दी है। इसी का एक और साक्ष्य, पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा और उसके गठजोड़ के मत प्रतिशत में भी बहुत ज्यादा न सही, फिर भी कुछ न कुछ गिरावट का ही होना है। खुद भाजपा के मत फीसद में यह गिरावट इसलिए और भी उल्लेखनीय हो जाती है कि 2024 में उसने तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़े हुए, पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर भी, पिछली बार के मुकाबले करीब 1 फीसद कम वोट हासिल किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में भाजपा को 37.36 फीसद वोट मिला था, जो इस चुनाव में घटकर 36.56 फीसद ही रह गया है।

अब इंडिया की राह क्या हो?

राववार का नरन्द्र मादा न तासरा बार प्रधानमंत्री का पद सफ्टाल लिया है और उनकी सुरक्षार ने

A photograph of Prime Minister Narendra Modi speaking at a podium with microphones. He is wearing a blue checkered Nehru jacket over a white kurta. The background is blurred, showing warm lights.

अनुमान लगाया जा रहा था कि दाना दल ज्यादा मंत्री पद चाहोंगे पर इनके एक-एक सदस्य को ही केबिनेट मंत्री बनाया गया है। फिलहाल तो कोई विवाद होता नहीं दिख रहा है। राकांपा जरूर नाराज है जिसे केवल एक राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था। इसलिये उसका कोई प्रतिनिधि रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ।

इंडिया के लिये असली संदेश तो यही है कि वह

एनडीए में विवादों के पनपने और उनके इस कदर बड़ा होने का इंतजार न करे जिससे सरकार गिरे। अगर यह होना है तो वह अपने समय व कारणों से होता रहेगा लेकिन विपक्ष को अपने तई प्रयासों को जारी रखना होगा। क्या हैं वे प्रयास? उसे वही करना है जो वह पिछले दो वर्षों से करती आई है। 2014 व 2019 के मुकाबले कांग्रेस को बड़ा जनादेश मिला है और दस वर्षों में उसके सदस्यों का आंकड़ा दहाई को छूने जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड या रायबरेली की एक सीट छोड़ने पर वहां से जो भी कांग्रेस प्रत्याशी लड़े, जीतेगा। इस तरह कांग्रेस 100 तक पहुंच जायेगी। दो राष्ट्रव्यापी यात्राओं के बाद राहुल का कद तो बढ़ा ही है, एक सर्वे में उन्हें पीएम के रूप में देखने वाले

